RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 256
दि. 17.02.2026, मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

'एआई में भारत सबसे आगे', एआई इम्पैक्ट एक्सपो पर पीएम मोदी ने गिनाई देश की ताकतें

(जीएनएस)।

नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में तकनीक की नई झलक देखने को मिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियो के AI पवेलियन का दौरा किया. यहां हेल्थ, शिक्षा और स्मार्ट होम से जुड़े आधुनिक मॉडल पेश किए गए. दौरे ने भारत में अक के बढ़ते दायरे और संभावनाओं को उजागर किया.

जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान जियो AI पवेलियन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हेल्थकेयर, एजुकेशन, कल्चर और स्मार्ट होम सॉल्यूशंस में कंपनी के AI-लेड ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया.

नई दिल्ली में आयोजित India AI Impact Summit 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियो इंटेलिजेंस पवेलियन का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कई अत्याधुनिक मॉडलों और समाधानों की लाइव प्रस्तुति देखी. यह दौरा भारत में तेजी से बढ़ते अक इकोसिस्टम और निजी क्षेत्र की भूमिका को रेखांकित करने वाला माना जा रहा है. आकाश अंबानी ने दिखाई अक की पूरी झलक, जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी को जियो के व्यापक AI इकोसिस्टम के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कैसे कंपनी का

AI स्टैक एंटरप्राइज इंटेलिजेंस से लेकर स्मार्ट होम तक समाधान दे रहा है. प्रधानमंत्री ने Jio AI Stack, Jio Sanskriti AI, Jio Arogya AI, Jio Shiksha और Jio AI Home जैसी पहलों का अवलोकन किया. ये प्लेटफॉर्म भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक कंटेंट को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और स्मार्ट जीवनशैली को सक्षम बनाने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं. हेल्थ, शिक्षा और संस्कृति में अक की ताकत, पवेलियन में प्रदर्शित मॉडलों ने दिखाया कि अक किस तरह अस्पतालों में बेहतर निदान, स्कूलों में पर्सनलाइज्ड लर्निंग और भारतीय भाषाओं के संरक्षण में मदद कर सकता है. जियो का फोकस ऐसी तकनीक विकसित करना है जो सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव और छोटे कस्बों तक भी पहुंचे. कंपनी ने 'AI for All' के अपने विजन को दोहराते हुए कहा कि उन्नत तकनीक को सुलभ और समावेशी बनाना ही असली डिजिटल परिवर्तन है.

निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका

Reliance Jio Innocomm Limited और इसकी मूल कंपनी Reliance Industries पहले भी तकनीक को जनसामान्य तक पहुंचाने पर जोर देती रही हैं. उद्योग जगत के नेताओं का मानना है कि भारत का AI भविष्य सार्वजनिक और निजी साझेदारी से ही मजबूत होगा. समिट में देश-विदेश की टेक कंपनियां, इनोवेटर्स और नीति-निमार्ता शामिल हुए, जिससे साफ है कि भारत वैश्विक AI मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है. प्रधानमंत्री का यह दौरा इसी दिशा में एक अहम संकेत माना जा रहा है.

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 17 फरवरी 2026 को मुंबई जाएंगे, जहां वे फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात करेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 17-19 फरवरी 2026 तक भारत के औपचारिक दौरे पर रहेंगे। वे भारत में हो रहे एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे और मुंबई में प्रधानमंत्री के साथ एक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। यह राष्ट्रपति मैक्रों का भारत का चौथा और मुंबई का पहला दौरा होगा।

17 फरवरी को लगभग 3:15 बजे, दोनों नेता मुंबई के लोक भवन में द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगे। इन बैठकों के दौरान, वे भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। उनकी चर्चा रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने और इसे नए तथा उभरते क्षेत्रों में और विस्तारित करने पर केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार साझा करेंगे।

लगभग शाम 5:15 बजे, दोनों नेता भारतझ्रफ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन करेंगे और दोनों देशों के व्यवसायिक नेताओं, स्टार्ट-अप, शोधकताओं और अन्य नवोन्मेषकों के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

राष्ट्रपति ने अलचिकि लिपि के शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (16 फरवरी, 2026) नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित अलचिकि लिपि के शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि संताल समुदाय की अपनी भाषा, साहित्य और संस्कृति है। हालांकि, अपनी लिपि के अभाव में संताली भाषा को प्रारंभ में रोमन, देवनागरी, उड़िया और बंगाली लिपियों में लिखा जाता था। नेपाल, भूटान और मॉरीशस में रहने वाले संताल समुदाय के लोग भी वहाँ प्रचलित लिपियों का उपयोग करते थे। ये लिपियां संताली भाषा के मूल शब्दों का सही उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पा रही थीं. साल 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मु ने अलचिकि लिपि का आविष्कार किया। तब से यह संताली भाषा के लिए उपयोग में लाई जा रही है। आज यह लिपि विश्वभर में संताल पहचान का सशक्त प्रतीक बन चुकी है और समुदाय में एकता स्थापित करने का प्रभावी माध्यम भी है।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों मंगलवार को भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन करेंगे

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को मुंबई जाएंगे, जहां वे फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारतझ फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन करेंगे और दोनों देशों के व्यवसायिक नेताओं, स्टार्ट-अप, शोधकताओं और अन्य नवोन्मेषकों के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

पीएम मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मैक्रों 17 फरवरी से तीन दिन के आधिकारिक दौरे पर भारत आ रहे हैं। वे 19 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ होराइजन-2047 रोडमैप में निर्धारित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार, 17 फरवरी को लगभग

3:15 बजे, दोनों नेता मुंबई के लोक भवन में द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगे। इन बैठकों के दौरान, वे भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके बाद लगभग शाम 5:15 बजे, दोनों नेता भारतझ फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन करेंगे।

उनकी चर्चा रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने और इसे नए तथा उभरते क्षेत्रों में और विस्तारित करने पर केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार साझा करेंगे।

उनका यह दौरा पिछले वर्ष फरवरी में पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के बाद हो रहा है। यह दौरा भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में आपसी विश्वास और गहराई को दशार्ता है।

भारतीय व्यापार सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, रक्षा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन सेवा और भारतीय व्यापार

सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।

राष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिष्ठित सेवाओं में चयन से उन्हें राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मिलता है। उन्होंने उन्हें यह याद रखने की सलाह दी कि ऐसे बहुत से युवा हैं जो ये सेवा करने का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है।

यूपी में फॉर्म 7 पर मची सियासी रार के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार, पूछा- इस पर चिल्लाहट क्यों?

यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के बीच फॉर्म 7 पर जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद् में इस पर जवाब दिया और सपा पर पलटवार किया.

(जीएनएस)।

भारत निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार उत्तर प्रदेश में जारी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 के दुरुपयोग का दावा किया है. अब इस पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है.

कांग्रेस का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने पूछा कि आखिर इसमें इतनी चिल्लाहट क्यों मच रही है. उन्होंने कहा कि सपा को कांग्रेस से सबक लेना चाहिए. आज विधान परिषद् में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है. अगर यही स्थिति रही तो सपा भी यहां शून्य हो जाएगी.

सीएम योगी ने कहा कि विपक्षी दल हमारे संवैधानिक मूल्यों पर प्रहार करने से नहीं चूक रहे. वर्तमान में प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है. इसमें राज्य सरकार की कोई

भूमिका नहीं होती. आयोग जो गाइडलाइन जारी करता है उसके अनुसार तंत्र उसका पालन करता है लेकिन सरकार उसका हिस्सा नहीं होती.

यूपी में रक्त्र पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा चीफ ने कहा- फर्जी साइन से वोट कटवा रही इखढ

सीएम ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में 2 करोड़ लोग 88 लाख से अधिक लोग या तो अनुपस्थित पाए गए या मृत पाए गए या फिर शिफ्ट हो गए. हमें आश्चर्य होता है कि सपा इनको अपना वोट बैंक बनाकर फर्जी वोटिंग कराती है. इसीलिए चिल्ला रही है कि फॉर्म 7 के नाम पर फर्जी काम हो रहा है.

सीएम योगी ने कांग्रेस का नाम लेकर कसा सपा पर तंज

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक व्यवस्था बनाई है. तीन प्रकार के फॉर्म दिए गए हैं.जिसमें फॉर्म, 6,7 और 8. फॉर्म 6 में आपको मतदाता होने का प्रमाण या नाम जुड़वाने के लिए देना होता है. फॉर्म 7 में अगर किसी का नाम कटवाना है तो उसका इस्तेमाल होता है. अगर कोई व्यक्ति भौतिक रूप से उपस्थित हो जाता है तो वह फॉर्म स्वतः निरस्त हो जाता है. मैं नहीं समझता कि आखिर इस पर इतनी चिल्लाहट क्यों हो रही है? आरोप प्रत्यारोप क्यों लग रहे हैं. यह नहीं हो सकता है कि हम अपने अनुरूप संवैधानिक संस्थाओं की परिभाषा गढ़ें.

सीएम ने इस दौरान कांग्रेस का नाम लेते हुए कहा कि मैं सपा से कहूंगा कि वह कम से कम कांग्रेस से सबक लें. विधान परिषद् तो कांग्रेस विहीन हो गया है. अगर आपको यहां और विधानसभा में सपा विहीन बनना है तो इस तरह के अनर्गल प्रलाप करते रहिए.

पीएम मोदी संसद में बोलने से बचते हैं, इंटरव्यू 'खोखले शब्दों' के अलावा कुछ नहीं : डेरेक ओ'ब्रायन

(जीएनएस)।

नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीटीआई को दिए उनके इंटरव्यू को लेकर सोमवार को निशाना साधते हुए उन्होंने इसे "खोखले शब्द" बताते हुए कहा कि वह संसद में बोलने के बजाय "भाग गए".

राज्यसभा में टीएमसी के नेता ओ'ब्रायन ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए उन्हें ह्यह्यटेलीप्रॉम्प्टर टाइकूनह्लह्ल भी कहा. ओ'ब्रायन ने इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया देते हुए पीटीआई-भाषा से कहा, ह्यह्यप्रधानमंत्री मोदी यानी ह्यटेलीप्रॉम्प्टर टाइकूनह्ल के खोखले शब्दों का एक और उदाहरण..., जो संसद में बोलने से कतराते हैं.ह्लह्ल

बता दें कि हाल में बजट सत्र के दौरानअभूतपूर्व घटनाक्रम में, विपक्षी सदस्यों की लगातार नारेबाजी के

दौरान, लोकसभा ने प्रधानमंत्री के पारंपरिक उत्तर दिए बिना ही, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव को पारित कर दिया था.

वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बाद में कहा कि उनके पास पुख्ता जानकारी थी कि कांग्रेस के कई सदस्य प्रधानमंत्री मोदी की सीट की ओर बढ़ सकते हैं और किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम दे सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उनसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने के लिए सदन में नहीं आने का अनुरोध किया था. राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के बाद पीएम मोदी ने जवाब दिया था. इस दौरान विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया था. पीएम ने रविवार को नवीनतम बजट और अपनी सरकार द्वारा हस्ताक्षरित कई वैश्विक व्यापार समझौतों को विकसित भारत की नींव बताया था और निजी क्षेत्र से अब अधिक आक्रामक और साहसिक रूप से आगे आने का अनुरोध किया.

प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू पर कांग्रेस संचार प्रभारी जयराम रमेश का वार कहा, बजट और ट्रेड डील से ध्यान भटकाने की कोशिश

(जीएनएस)।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के पीटीआई साक्षात्कार को "हताश पीआर कवायद" बताया है। कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे 'सावधानीपूर्वक लिखी गई और हताश पीआर कवायद" करार दिया है। पार्टी का आरोप है कि यह इंटरव्यू वास्तविक सवालों से बचने और सुर्खियां प्रबंधित करने का प्रयास है।

कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री व्यापार समझौते और बजट को लेकर विपक्ष के हमलों से घिरे हुए हैं, इसलिए वह अपने पसंदीदा हथकंडे यानी हेडलाइन मैनेजमेंट का सहारा ले रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि इस वर्ष का बजट निराशाजनक रहा है और बाजार व निवेशकों की प्रतिक्रिया भी उत्साहजनक नहीं रही।

ध्यान हटाने की कोशिश

जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि

प्रधानमंत्री किसानों और अन्य वर्गों से जुड़े मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह कोई इंटरव्यू नहीं बल्कि एक सोचा-समझा प्रचार अभ्यास है।

व्यापार वार्ता पर मोदी के आरोपों को बताया 'अनुचित और गलत'

प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान व्यापार वाताओं की आलोचना किए जाने पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए उनके आरोपों को 'अनुचित और गलत" करार दिया है। पार्टी का कहना है कि यूपीए शासन में भारत ने एक आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में कई महत्वपूर्ण व्यापार समझौते किए थे।

पूर्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने बयान जारी कर कहा कि यूपीए काल में भारत की अर्थव्यवस्था ने औसतन आठ प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर्ज की और 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद भी मजबूती से उभरी। उन्होंने मौजूदा सरकार द्वारा अमेरिका के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते को 'अपारदर्शी" बताते हुए उसके विवरण सार्वजनिक करने की मांग की। उनका आरोप है कि कृषि, कपास और वस्त्र जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

भिवाड़ी अग्निकांड के मृतकों के परिजनों को राजस्थान सरकार देगी 3-3 लाख रुपये मुआवजा

(जीएनएस)।

भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग से हुई जनहानि को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने "अत्यंत हृदयविदारक और दुखद" बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुःख की इस घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूरी संवेदना से खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से तीन-तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन को भी प्रत्येक पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता तत्काल सुनिश्चित करने को कहा गया है।

अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र की इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है, और राज्य सरकार ने पीड़ितों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।

भिवाड़ी में कैसे हुआ ये हादसा?

बता दें राजस्थान के भिवाड़ी में सोमवार को एक रासायनिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से सात श्रमिकों की मौत हो गई। इस हादसे में दस अन्य मजदूरों के अभी भी फंसे होने की आशंका जताई गई थी। यह घटना सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे हुई, जब फैक्ट्री में 20-25 कर्मचारी काम कर रहे थे।

चंद मिनटों में विकराल हो गई थी आग

आग कुछ ही मिनटों में निजी औद्योगिक इकाई से तेजी से फैल गई और फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ श्रमिक अपनी जान बचाने में सफल रहे। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुमिता मिश्रा ने बताया, घटना का पता पुलिस की नियमित गश्त के दौरान चला।

पुलिस, दमकल कर्मी, मेडिकल टीमें और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत प्रयासों के लिए क्षेत्र को घेर लिया। डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया।

हालांकि, आग लगने के सटीक कारणों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। तिजारा के पुलिस उपाधीक्षक शिवराज सिंह घटनास्थल पर प्रारंभिक जांच की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक और अपर जिला मजिस्ट्रेट सहित वरिष्ठ जिला अधिकारी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।

जिला प्रशासन ने आग के कारणों और सुरक्षा प्रोटोकॉल में संभावित चूकों का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रियल जांच की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 फरवरी को इजरायल का दौरा करेंगे, बोले बेंजामिन नेतन्याहू

(जीएनएस)।

यरूशलेमः इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 से 26 फरवरी तक दो दिवसीय यात्रा पर इजरायल आएंगे। उन्होंने यह घोषणा प्रमुख अमेरिकी यहूदी संगठनों के अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए की। नेतन्याहू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, "संसद में भाषण देने की तैयारी चल रही है। अगले सप्ताह यहां कौन आ रहा है? नरेंद्र मोदी।"

नेतन्याहू ने कहा, "इजराइल और भारत के बीच जबरदस्त गठबंधन है, और हम हर तरह के सहयोग पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब, आप जानते हैं, भारत कोई छोटा देश नहीं है। इसकी आबादी 1.4 अरब है। भारत बेहद शक्तिशाली और बेहद लोकप्रिय है।"

प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्राः प्वाइंटर्स में समझिए

प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में इजरायल की यह पहली

यात्रा होगी।

प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक, रक्षा और तकनीकी संबंधों को नई गति मिल सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी बार 2017 में इजराइल का दौरा किया था, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 25 साल पूरे होने का प्रतीक था।

पिछली यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू ने रक्षा, साइबर सुरक्षा, कृषि और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर बातचीत की थी।

इस बार, दोनों नेताओं के पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा करने की उम्मीद है।

सितंबर में दोनों देशों के बीच हुई थी ये संधि

दोनों देशों के बीच सितंबर में ही द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) हुई थी। इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर हस्ताक्षर हुए थे। इससे पहले पिछले साल नवंबर में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की इजरायल यात्रा के दौरान भी कई अहम समझौते हुए, जिसमें मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) और टीओआर पर हस्ताक्षर किए गए थे।

गौरतलब है कि भारत और इजरायल के बीच रिश्ते काफी मजबूत और मधुर रहे हैं। पीएम मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अच्छे मित्र हैं और एक-दूसरे से बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी की इजरायल यात्रा के बाद दोनों देशों को क्या-क्या फायदा मिलता है और क्या घोषणाएं होती हैं।

'सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव के लिए एआई का विस्तारः सार्वजनिक-निजी भागीदारीर विषय पर एक उच्च-स्तरीय पैनल चर्चा का आयोजन

(जीएनएस)।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026 के अंतर्गत "सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव के लिए एआई का विस्तारः सार्वजनिक-निजी भागीदारी" विषय पर एक उच्च-स्तरीय पैनल चर्चा का आयोजन किया।

भारत सरकार 16 से 20 फरवरी, 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026 की मेजबानी कर रही है। यह वैश्विक दक्षिण में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है। इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं, नीति निमार्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और नवप्रवर्तकों एक साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की परिवर्तनकारी क्षमता पर विचार-विमर्श करेंगे, जिसमें समावेशी और सतत विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा।

एक प्रमुख भागीदार मंत्रालय के रूप में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एक उच्च-स्तरीय पैनल चर्चा, प्रमुख पहलों के शुभारंभ और अपने समर्पित प्रदर्शनी स्टॉल पर एआई-संचालित स्वास्थ्य सेवा समाधानों के प्रदर्शन के माध्यम से शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली ने अभिलेखों के बुनियादी डिजिटलीकरण और बेहतर डेटा रिपोर्टिंग से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर परस्पर सुगम डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने याद दिलाया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभव मानक को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट के माध्यम से खुले मानकों, परस्पर सुगमता, गोपनीयता-आधारित डिजाइन और जनरेटिव एआई सहित उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देकर और कार्यान्वित किया गया।

उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्वास्थ्य के लिए एक मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में विकसित हो चुका है, जिसमें 859 मिलियन से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट खाते 878 मिलियन से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड से जुड़े हुए हैं। देश भर में 1.80 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म को एकीकृत किया जा रहा है। एआई-सहायता प्राप्त क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम द्वारा संचालित ई-संजीवनी ने 2.2 लाख से अधिक पंजीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के माध्यम से 449 मिलियन से अधिक टेलीकंसल्टेशन को सक्षम बनाया है, जिससे यह प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में विश्व की सबसे बड़ी टेलीमेडिसिन पहल बन गई है।

उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रणालियां सूचना के संग्रहण और प्रसारण को सक्षम बनाती हैं जबकि एआई इसकी बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्या और कार्रवाई को संभव बनाता है। उन्होंने कहा कि एआई में स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों पर बोझ कम करने और चिकित्सक-रोगी संबंध को मजबूत करने की क्षमता है, न कि उसे प्रतिस्थापित करने की।

उदाहरण देते हुए, उन्होंने एआई-आधारित डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग के लिए मधुनेत्रएआई, तपेदिक का पता लगाने के लिए एआई-सक्षम हैंडहेल्ड एक्स-रे और कफ अगेंस्ट टीबी (सीए-टीबी) जैसे ध्वनिक स्क्रीनिंग उपकरणों और तेजी से महामारी संबंधी अलर्ट के लिए एआई-एकीकृत निगरानी प्रणालियों का उल्लेख किया। उन्होंने एम्स दिल्ली, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ और एम्स ऋषिकेश में स्वास्थ्य सेवा में एआई के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना पर भी प्रकाश डाला।

सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने उद्योग और राज्य प्रतिनिधियों को सरकारी प्रणालियों के साथ काम करने, खरीद और डेटा ढांचे में सुधार करने और जमीनी स्तर पर सबसे उपयोगी एआई समाधानों की पहचान करने के अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में समावेश और समानता के साधन के रूप में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत का जोर, विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप, डिजिटल स्वास्थ्य और एआई के क्षेत्र में भारत की प्रगति का मार्गदर्शन करता रहेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ डॉ. सुनील कुमार बरनवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) स्वास्थ्य सेवा वितरण में दक्षता को काफी हद तक बढ़ा सकती है और विशेष रूप से बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में त्वरित, डेटा-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बना सकती है। उन्होंने कहा कि एआई-संचालित विश्लेषण लाभार्थियों की पहचान को मजबूत कर सकता है, दावों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर सकता है, धोखाधड़ी का पता लगा सकता है और सेवा उपयोग की निगरानी कर सकता है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और समग्र प्रणाली प्रदर्शन में सुधार होगा।

उन्होंने एआई समाधानों के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत डेटा प्रबंधन और गोपनीयता सुरक्षा उपायों द्वारा समर्थित अंतरसंचालनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के महत्व पर जोर दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के व्यापक और जटिल स्वरूप को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि संसाधनों के बेहतर आवंटन, सेवाओं के बेहतर लक्ष्यीकरण और देश भर में बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचार आवश्यक हैं।

खदरा लखनऊ व्यापार मंडल की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने ली शपथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत उपस्थित रहे ये लोग

(जीएनएस)।

लखनऊ के खदरा परिक्षेत्र में नौ व्यापार मंडलों का गठन किया गया, जिनके नवनियुक्त पदाधिकारियों ने शपथ ली। खदरा लखनऊ व्यापार मंडल परिक्षेत्र में नौ संगठनों का गठन किया गया है। नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह सीतापुर रोड के खदरा चुंगी में आयोजित किया गया। यहां उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, विधायक नीरज बोरा व महापौर सुषमा खर्कवाल भी उपस्थित रहीं।

खदरा परिक्षेत्र लखनऊ व्यापार मंडल के संरक्षक- मुसव्विर अली उर्फ मंशू (पार्षद), मो. सगीर खान, विधिक सलाहकार- विजय तिवारी, हामिद रज्जाक एवं प्रवक्ता- मो. असलम, दीनदयाल नगर खदरा लखनऊ व्यापार मंडल अध्यक्ष- विशाल,

वरिष्ठ उपाध्यक्ष- मो. तारिक उपाध्यक्ष, मजहर वरिष्ठ, महामंत्री- अनवार अली, शकील, मंत्री-संजय जैन, सचिव- अहमद, कोषाध्यक्ष- मो. अशफाक, प्रचार मंत्री- उमेश अग्रवाल, संरक्षक- सरोज, सतीश ने शपथ ली।

अध्यक्ष- फैजान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष- मुस्तकीम, उपाध्यक्ष- मुदस्सिर, वरिष्ठ महामंत्री- शहजाद, महामंत्री- शारिक गाजी, मंत्री- मो. अरसलान, सचिव- निजाम, कोषाध्यक्ष- मो. हारून, दीपू गुप्ता, प्रचार मंत्री- शानू ने शपथ ली।

इसके अलावा शिवनगर रोड खदरा लखनऊ व्यापार मंडल अध्यक्ष- डॉ. शफीक अंसारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष- अनस, उपाध्यक्ष- शमशुल अंसारी, वरिष्ठ महामंत्री- अरविन्द कुमार, महामंत्री- बुद्धिसागर मिश्र, बड़ी पकरिया रोड खदरा लखनऊ व्यापार मंडल अध्यक्ष- इस्माईल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष- दीपू जायसवाल, उपाध्यक्ष- इस्तिखार, वरिष्ठ महामंत्री- अजीम, महामंत्री- आशीष वर्मा।

कर्बला रोड खदरा लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अंजुम वरिष्ठ, उपाध्यक्ष- शोएब सिद्दीकी, उपाध्यक्ष- बिलाल,

वरिष्ठ महामंत्री- फुरकान महामंत्री, अवध वाटिका रोड व्यापार मंडल अध्यक्ष- यूसुफ अंसारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष- शकील, उपाध्यक्ष- मो. शज्जू, वरिष्ठ महामंत्री- मो. आसिफ, महामंत्री- सादान मंत्री, सीतापुर रोड खदरा (पश्चिम) लखनऊ व्यापार मंडल अध्यक्ष- आशीष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष- रिजवान कुरैशी, उपाध्यक्ष- मो. आमिर, वरिष्ठ महामंत्री- राहुल, महामंत्री- शहनवाज आलम ने शपथ ली।

रामलीला ग्राउंड रोड खदरा लखनऊ व्यापार मंडल अध्यक्ष- आशीष जायसवाल , वरिष्ठ उपाध्यक्ष- इश्तियाक खान, उपाध्यक्ष- ध्रुव मिश्र, वरिष्ठ महामंत्री- मो. इदरीस, महामंत्री- शहाबुद्दीन।

सीतापुर रोड खदरा (पूरब) लखनऊ व्यापार मंडल

अध्यक्ष- राकेश कुमार गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष- जीलानी, उपाध्यक्ष- जीमल अहमद, वरिष्ठ महामंत्री- मुमताज, महामंत्री- सलमान ने पद की शपथ ली।

रोबोटिक्स एआई के माध्यम से मूल्यवर्धन करके स्वास्थ्य सेवा में एक नया आयाम जोड़ेगीः डॉ. जितेंद्र सिंह

डॉ. जितेंद्र सिंह का कहना है कि नई दिल्ली के एम्स के रेडियोलॉजिस्टों द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित टेली-रोबोटिक अल्ट्रासोनोग्राफी (टीयूएस) का संचालन करके अंटार्कटिका के मैत्री स्टेशन पर 12,000 किलोमीटर दूर तैनात लोगों की जांच करना, दूरस्थ स्वास्थ्य सेवा में एक नए युग की शुरूआत है

(जीएनएस)।

जितेंद्र सिंह ने दिल्ली से अंटार्कटिका तक लाइव टेली-रोबोटिक अल्ट्रासाउंड देखा, जो विज्ञान और सरकार के समग्र दृष्टिकोण को दशार्ता है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अक्सर दोहराते हैं

नई दिल्ली, 16 फरवरीः कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित स्वास्थ्य सेवा और अत्याधुनिक विज्ञान में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित करते हुए, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने

आज अपने विचार व्यक्त किए।

केंद्रीय मंत्री नई दिल्ली स्थित एम्स को अंटार्कटिका के मैत्री अनुसंधान केंद्र से जोड़ने वाली स्वदेशी रूप से विकसित टेली-रोबोटिक अल्ट्रासोनोग्राफी प्रणाली के सफल लाइव प्रदर्शन को देख रहे थे।

राष्ट्रीय राजधानी में चल रही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर चचाओं का जिक्र करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस तरह के नवाचार एआई, रोबोटिक्स और वास्तविक समय की चिकित्सा विशेषज्ञता के संगम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा की पहुंच भौगोलिक बाधाओं से परे विस्तारित होती है।

नई दिल्ली एम्स और दिल्ली आईआईटी द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र के सहयोग से संयुक्त रूप से विकसित इस प्रणाली ने दिल्ली में बैठे एक डॉक्टर को अंटार्कटिका में 12,000 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित एक स्वयंसेवक की वास्तविक समय में अल्ट्रासाउंड जांच करने में सक्षम बनाया। अल्ट्रासाउंड प्रोब से सुसज्जित रोबोटिक भुजा छह डिग्री की स्वतंत्रता प्रदान करती है, जो एक विशेषज्ञ सोनोग्राफर के हाथों की सटीक गतिविधियों की हूबहू नकल करने में सक्षम है। बल-संवेदन सुरक्षा सुविधाओं और एक सेकंड से भी कम की देरी से प्रदान की जाने वाली नैदानिक रूप से विश्वसनीय इमेजिंग के साथ, यह प्रणाली आपातकालीन स्थिति में किए जाने वाले आकलन को सुगम बनाती है, जिसमें फास्ट स्कैन, पेट के अंगों का मूल्यांकन, हृदय संबंधी आकलन और आघात की जांच शामिल है।

दुर्गम और दूरस्थ वातावरणों के लिए डिजाइन की गई यह तकनीक, यह तय करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती है कि किसी मरीज का इलाज स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है या उसे स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से अंटार्कटिका में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां एयरलिफ्ट करना महंगा होने के साथ-साथ लॉजिस्टिक रूप से भी जटिल होता है। किफायती, मजबूत और विस्तार योग्य होने को ध्यान में रखते हुए निर्मित यह प्रणाली, सीमावर्ती क्षेत्रों, आपदा क्षेत्रों, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों और देश भर में मोबाइल चिकित्सा इकाइयों में तैनाती की क्षमता रखती है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों के साथ माननीय राष्ट्रपति जी से मिलकर उन्हें समिति का 13वाँ प्रतिवेदन सौंपा

समिति के कार्य में गति लाकर राजभाषा को और भी सशक्त व आधुनिक बनाने की दिशा में समिति ने बीते 6 वर्षों में राष्ट्रपति जी को 4 प्रतिवेदन सौंपे हैं, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों के साथ माननीय राष्ट्रपति जी से मिलकर उन्हें समिति का 13वाँ प्रतिवेदन सौंपा।

प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा 'आज संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों के साथ माननीय राष्ट्रपति जी से मिलकर उन्हें समिति का 13वाँ प्रतिवेदन सौंपा। समिति के कार्य में गति लाकर राजभाषा को और भी सशक्त व आधुनिक बनाने की दिशा में समिति ने बीते 6 वर्षों में राष्ट्रपति जी को 4 प्रतिवेदन सौंपे हैं, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है।

'नवाबों के शहर' लखनऊ पहुंचे सिद्धांत चतुर्वेदी...चढ़ा इश्क का खुमार, मृणाल ठाकुर संग शेयर कीं स्पेशल फोटोज

(जीएनएस)।

फिल्म 'दो दीवाने शहर में' संजय लीला भंसाली की प्रोडक्शन में बनी है. यह एक खूबसूरत लव स्टोरी है, जिसमें भावनाओं और रिश्तों की गहराई दिखाई गई है. कई दिनों से लगातार मृणाल और सिद्धांत फिल्म की प्रमोशन को लेकर लगे हुए हैं. दोनों ने वेलेंटाइन वीक के सारे डे साथ में मनाए थे, जिसे सोशल मीडिया पर काफी प्यार मिला था.

अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी इन दिनों आगामी फिल्म 'दो दीवाने शहर में' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. रोमांटिक ड्रामा फिल्म में वे मृणाल के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. अभिनेता हाल ही में लखनऊ की सैर पर गए हुए हैं. उन्होंने सोमवार को इंस्टाग्राम पर इसकी झलकियां शेयर कीं. इन तस्वीरों में वे अकेले लखनऊ की गलियों में घूमते दिख रहे हैं, तो कुछ फोटोज में उनकी को-स्टार मृणाल ठाकुर भी साथ नजर आ रही हैं. सिद्धांत ने इन तस्वीरों के साथ लिखा, "मुझे लखनऊ और घूमना है.

बस 4 दिन बाकी हैं."

सिद्धांत का यह पोस्ट फैंस को काफी पसंद आ रहा है. वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. फिल्म 'दो दीवाने शहर में' संजय लीला भंसाली की प्रोडक्शन में बनी है. यह एक खूबसूरत लव स्टोरी है, जिसमें भावनाओं और रिश्तों की गहराई दिखाई गई है. कई दिनों से लगातार मृणाल और सिद्धांत फिल्म की प्रमोशन को लेकर लगे हुए हैं. दोनों ने वेलेंटाइन वीक के सारे डे साथ में मनाए थे, जिसे सोशल मीडिया पर काफी प्यार मिला था.

फिल्म 'दो दीवाने शहर में' का निर्देशन रवि उद्यावर ने किया है. यह फिल्म दो ऐसे लोगों की कहानी है जो यह सिखाती है कि हर वक्त परफेक्ट होना जरूरी नहीं है. इसके कुछ गाने रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें दर्शकों की तरफ से काफी प्यार मिल रहा है. साथ ही, इसमें सिद्धांत और मृणाल की केमिस्ट्री भी सबको बहुत पसंद आ रही है. अब देखना होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में कैसा प्रदर्शन करेगी.

इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में हैं. इन दोनों के अलावा फिल्म में ईला अरुण, जॉय सेनगुप्ता, आयशा रजा, विराज गेहलानी, संदीपा धर, दीपराज राणा, मोना अम्बेगांवकर, अचिंत कौर, और नवीन कौशिक भी नजर आएंगे. अब देखना होगा कि फिल्म को दर्शक कितना प्यार देते हैं. रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'दो दीवाने शहर में' 20 फरवरी को रिलीज होगी.

लखनऊः मेट्रो टिकट के लिए लाइन में लगने का झंझट खत्म, मोबाइल से बुक करें क्यूआर कोड और सीधे करें सफर

(जीएनएस)।

लखनऊ के मेट्रो यात्रियों के लिए सोमवार से एक नई सुविधा की शुरूआत हुई है. अब आपको टोकन के लिए लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने क्यूआर-आधारित टिकटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे यात्री घर बैठे ही मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक कर सकेंगे.

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (वढटफ्छ) के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने सोमवार को हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर क्यूआर-आधारित टिकटिंग प्रणाली का औपचारिक उद्घाटन किया. इस नई व्यवस्था के तहत यात्री अब लखनऊ मेट्रो के आधिकारिक मोबाइल ऐप, टिकट वेंडिंग मशीन (ळश्ट) और टिकट काउंटर से क्यूआर टिकट बुक कर सकते हैं. मोबाइल ऐप से बुक किए गए टिकट डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध होंगे, जबकि काउंटरों से कागज वाले क्यूआर टिकट मिलेंगे. यात्री इन टिकटों को ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन (अऋ्छ) गेट पर लगी पीली पट्टी वाले स्कैनर पर स्कैन करके स्टेशन के भीतर प्रवेश और निकास कर सकेंगे.

मोबाइल ऐप और टीवीएम से

मिलेगी सुविधा

लखनऊ मेट्रो प्रशासन ने सभी स्टेशनों पर नई क्यूआर-समर्थित टिकट वेंडिंग मशीनें (ळश्ट) स्थापित की हैं. इन मशीनों पर यात्रियों को यूपीआई (वढक) के जरिए भुगतान करने की सुविधा भी मिलेगी. जो लोग तकनीकी रूप से कम सहज हैं, वे टिकट काउंटर से पेपर-आधारित क्यूआर टिकट ले सकते हैं. खास बात यह है कि टोकन आधारित पुरानी व्यवस्था भी अन्य मशीनों पर पहले की तरह ही चालू रहेगी, जिससे यात्रियों के पास सफर के लिए कई विकल्प मौजूद होंगे.

डिजिटल इंडिया की ओर एक और कदम

इस अवसर पर एमडी सुशील कुमार ने कहा कि यह कदम 'स्मार्ट ट्रैवल' की अवधारणा पर आधारित है. यात्री अब कहीं से भी टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे यात्रा तेज और सुविधाजनक हो जाएगी. उन्होंने इसे 'डिजिटल इंडिया' के दृष्टिकोण के अनुरूप बताया, जहां सेवाएं सिर्फ 'एक टैप' की दूरी पर हैं. इस प्रणाली से स्टेशनों पर भीड़ कम होगी और यात्रियों का समय भी बचेगा. पीली पट्टी वाले एएफसी गेट्स को विशेष रूप से इन टिकटों की स्कैनिंग के लिए तैयार किया गया है.

जल्द शुरू होगी 'वन नेशन, वन कार्ड' सुविधा

कानपुर और आगरा मेट्रो के सफल मॉडल के बाद, अब लखनऊ में भी जल्द ही नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा शुरू की जाएगी. सुशील कुमार ने बताया कि अगले चरण में इस सुविधा के आने से यात्री देश भर के उन सभी मेट्रो सिस्टम में सफर कर सकेंगे जहां एनसीएमसी की सुविधा उपलब्ध है. यह 'वन नेशन, वन कार्ड' के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, जिससे यात्रियों को हर शहर के लिए अलग कार्ड रखने

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com•navsarjansanskruti2016@yahoo.com•Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

पाक सेना अपने बल पर साथियों को छुड़ा नहीं पाई

पाकिस्तान की आर्मी इतनी बहादुर है कि जब बीएलए यानि बलोच लिबरेशन आर्मी चाहती है, उन्हें ठोंकती है और नाक रगड़वा कर छोड़ती है। तालिबान सरकार को जब गुस्सा आता है तो वह अपने लड़ाकों को भेजकर पीटती है और दर्जनों जब मारे जाते हैं तो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुल्ला आसिम मुनीर अरब देशों से गुहार लगाता है कि हमें बख्श दो अब गलती नहीं होगी, लेकिन झूठे नैरिटिव गढ़ने के ये इतने चतुर शिल्पी हैं कि भारत के साथ जितनी लड़ाईयां हुईं, उन सभी में जीत का दावा करते हैं और बाजार से खरीद कर सैन्य अधिकारी तमगे लगा लेते हैं। पोल पट्टी खुलने के डर से इस झूठ को फर्जी रूप से सही बनाने के लिए स्थाई भाव की जो साजिश रची गई है, उसी के तहत 1965, 1971 और कारगिलद्रास बटालिक युद्ध को जीतने का दावा अपने बच्चों की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है और यदि कोई पत्रकार हिम्मत करके सवाल पूछ लेता है तो उसे सैन्य प्रातिष्ठान न सिर्फ धमकाता है बल्कि उसको तरह-तरह से प्रताड़ित किया जाता है। अब इनकी सेना की वास्तविकता यह है कि इनके 17 सैनिकों को बीएलए ने हिरासत में ले लिया और 10 सैनिकों को मुक्त करके सैन्य प्रातिष्ठान को चेतावनी दी है कि यदि 7 और सैनिकों को छुड़ाना है तो उनके कैदियों को एक सप्ताह के अन्दर रिहा करो।

सच तो यह है पाकिस्तान का जैसा चरित्र है, वैसी ही उसकी फौज भी है। वह कुरान की कसम खाकर जान तो बीएलए से कई बार बचा चुकी है किन्तु अब बीएलए उनके झांसे में नहीं आती इसलिए अब सेना और बीएलए में जो भी सौदेबाजी होती है, वह 'एक हाथ से दे और दूसरे हाथ से ले' के सिद्धांत पर होती है। गत वर्ष जब पाक ट्रेन को ही ब्लूचिस्तान में बीएलए ने अपहरण किया था तब भी सेना अपने बल पर अपने साथियों को छुड़ा नहीं पाई थी। आए दिन पाक सेना खासकर पंजाब प्रांत के जवानों को बीएलए के लोग पीटते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पाक सेना अपने पड़ोसियों से पिटती है तो बाप-बाप चिल्लाती है और 'सीज फायर' के लिए गिड़गिड़ाने लगती है लेकिन शेखी ऐसी बघारते हैं कि वह युद्ध तो किसी देश से हारते ही नहीं, अपने देश की जनता को पाकिस्तान की सेना यह बताती है कि ब्लूचिस्तान में जो भी गड़बड़ चल रही है, उसके लिए भारत जिम्मेदार हैं। वह वास्तविकता को महसूस करने के लिए तैयार ही नहीं है। कल्पना करें, यदि भारत ब्लूचिस्तान में अलगाववादी गतिविधियां कराता तो क्या अभी तक पाकिस्तान का विखंडन न हो गया होता! वास्तविकता यह है कि बीएलए ईंरान से अवैध तेल हासिल कर उनसे धन कमाते हैं और पाकिस्तान की सेना को तबाह करते हैं। यही नहीं बीएलए चीन से भी उगाही करके उन्हें ब्लूचिस्तान में काम करने की अनुमति देता है। उसको मोटी कमाई हो रही है। इसलिए जब जनरल आसिम मुनीर और प्राधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने अमेरिका को कच्चे तेल और अपना रेयर अर्थ मिनरल निकालने का आग्राह किया तब बलोच मुक्ति आंदोलन के नेताओं ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर आग्राह किया कि वह जनरल मुनीर और प्राधानमंत्री शरीफ पर भरोसा न करें क्योंकि आप बीएलए से लड़कर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। पाक सेना बीएलए से आप के लोगों को सुरक्षा भी नहीं दे पाएगी। इसलिए यदि खनिज उत्खनन में आप वुछ करना चाहते हैं तो बीएलए से समझौता कर ले। इस पत्र के बाद ही ट्रंप का माथा ठनका था। यही कारण है आजकल ट्रंप पाकिस्तान को उस तरह चने की झाड़ पर नहीं चढ़ाता जैसा कि उन्होंने 2025 में अपने पूरे परिवार को पाकिस्तान में खनिज हासिल करने की उम्मीद से काम पर सव्रिय कर दिया था। बहरहाल पाकिस्तान की आमा इतनी जाहिल हो चुकी है कि वह कभी भारत से पिटती है तो पीठ झाड़ कर दावा करती है कि उसने तो मैदान मार लिया, बीएलए सैनिकों को ही मारती है इसलिए पंजाब सहित सारे क्षेत्रों के सैनिक बीएलए से पिटने के बाद भी खुलकर यह मानने को तैयार नहीं है कि ब्लूचिस्तान में अलगाववाद की आंधी यू ही नहीं आई है, इसका मुख्य कारण है बलूचों की समस्याओं को सुने बिना ही उन्हें आतंकी घोषित कर दिया गया।

तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे पीएम मोदी, उनकी जगह भारत से ये नेता होंगे शामिल

(जीएनएस)।

भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिसरी 17 फरवरी को तारिक रहमान के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

भारत के विदेश मंत्रालय और बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मीडिया सेल ने इसकी पुष्टि की है.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, "लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 17 फरवरी 2026 को ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान के नेतृत्व में बनी नव-निर्वाचित बांग्लादेश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे."

इस बयान में आगे कहा गया है, "लोकसभा अध्यक्ष की इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भागीदारी भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच गहरी और स्थायी मित्रता को रेखांकित करती है. यह उन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि भी है, जो हमारे दोनों देशों को जोड़ते हैं."

"साझा इतिहास, संस्कृति और परस्पर सम्मान से जुड़े पड़ोसी देशों के रूप में, भारत तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश के एक निर्वाचित सरकार की ओर बढ़ने का स्वागत करता है, जिनकी सोच और मूल्यों को बांग्लादेश की जनता ने भारी जनादेश दिया है."

बांग्लादेश के तेरहवें संसदीय चुनाव में बीएनपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे.

बांग्लादेश में नए कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने 13 देशों के शासनाध्यक्षों को आमंत्रित किया है.

ढाका में मौजूद बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित के अनुसार, अब तक जिन देशों को आमंत्रण भेजा गया है, उनमें चीन, सऊदी अरब, भारत, पाकिस्तान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान शामिल हैं.

इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों कल यानी 16 फरवरी से भारत की यात्रा पर आ रहे हैं.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने मैक्रों के दौरे का पूरा शेड्यूल जारी किया है जिसमें वो 16 फरवरी को देर रात दिल्ली पहुंच रहे हैं और 17 फरवरी को उनका मुंबई में कार्यक्रम है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में मैक्रों के साथ होंगे, जहां राजभवन के दरबार हॉल में एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे और प्रेस बयान जारी किया जाएगा.

मैक्रों का दौरा 19 फरवरी तक रहने वाला है और वो शाम को पेरिस रवाना होंगे.

इसलिए कुछ लोग अनुमान लगा रहे थे कि अंतरारष्ट्रीय दौरे की व्यस्तता के चलते पीएम मोदी शायद तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में न जा पाएं. हालांकि भारत की तरफ से खबर लिखे जाने तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

शुक्रवार को चुनाव के नतीजे आने के बाद पीएम मोदी ने तारिक रहमान को फोन कर चुनाव में जीत के लिए बधाई भी दी थी. बीएनपी ने पीएम मोदी को इसके लिए शुक्रिया भी कहा है.

बीबीसी बांग्ला संवाददाता शुभज्योति घोष ने शनिवार को पुष्टि की थी कि बीएनपी के चेयरपर्सन ऑफि स ने शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी को भी आमंत्रण भेजे जाने की जानकारी दी है.

बीएनपी अध्यक्ष के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर हुमायूं कबीर ने भी पुष्टि की थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तारिक के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा.

हालांकि अभी तक भारत की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद भारत ने बीएनपी के साथ संवाद के रास्ते खोले हैं. बीएनपी की जीत पर बधाई देने वाले शुरूआती नेताओं में पीएम मोदी रहे हैं.

तारिक रहमान ने भी रचनात्मक रूप से भारत के साथ बहुआयामी रिश्ते को मजबूत करने पर जोर दिया है.

शपथ ग्रहण के सवाल पर बीएनपी के नेता एएनएम एहसानुल हक ने शनिवार को ढाका में पत्रकारों के साथ बातचीत में उम्मीद जताई थी कि पीएम मोदी को आमंत्रण दिया जाएगा.

दक्षिण एशिया के नेताओं को आमंत्रित करने के सवाल पर उन्होंने कहा, "मुझे ठीक ठीक तो नहीं पता है लेकिन उम्मीद है कि वे सभी को बुलाएंगे. पीएम मोदी को भी बुलाया जाना चाहिए. ये एक सामान्य शिष्टाचार है और आयोजक ऐसा करेंगे."

बीएनपी ने अपने चुनावी अभियान में 'सभी से मित्रता' की नीति का वादा किया था.

पहले भी बीएनपी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से संकेत दिया गया था कि शपथ ग्रहण समारोह में सार्क (दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन) देशों के नेताओं को आमंत्रण भेजा जाएगा, जिनमें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का भी नाम होगा.

साल 2014 में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद सार्क देशों के नेताओं का ऐसा जुटान, पहली बार ढाका में होने की संभावना जताई जा रही है.

रक्षा मंत्री ने बेंगलुरु में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान में स्वदेशी सैन्य गैस टरबाइन इंजन विकास परियोजनाओं की समीक्षा की

राष्ट्रीय सुरक्षा को आत्मनिर्भरता के माध्यम से मजबूत करने के लिए जीटीआरई की सराहना की

सरकार एयरो इंजन विकास में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है

ऑपरेशन सिंदूर ने रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया है, विश्व स्तरीय स्वदेशी प्रणालियों के निर्माण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है

,

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 6 फरवरी, 2026 को बेंगलुरु स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान (जीटीआरई) का दौरा किया और स्वदेशी सैन्य गैस टरबाइन इंजन विकास से सम्बंधित परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री को प्रतिष्ठान की निमार्णाधीन परियोजनाओं, भारतीय उद्योग, शिक्षा जगत और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ हुए संवाद और रक्षा बलों को प्रदान किए जा रहे समर्थन के बारे में जानकारी भी दी गई। उन्होंने विभिन्न स्वदेशी इंजनों और उनके पुर्जों की प्रदर्शनी का भी दौरा किया और कावेरी इंजन के पूर्ण आफ्टरबर्नर परीक्षण को देखा।

रक्षा मंत्री ने वैज्ञानिकों और अधिकारियों से बातचीत करते हुए आत्मनिर्भरता से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के लिए जीटीआरई की सराहना की और डीआरडीओ को देश की रणनीतिक क्षमता का आधार बताया। उन्होंने वर्तमान तेजी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में एयरो इंजन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के महत्व पर बल दिया और कहा कि देश में एयरो इंजनों के विकास को प्राथमिकता देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं में परिवर्तन आ रहा हैं और नए इकोसिस्टम विकसित हो रहे हैं। स्वदेशी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों वाले राष्ट्र सुरक्षित, संरक्षित और आत्मनिर्भर बने रहेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को दोहराया।

जीटीआरई के महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्र में हुए प्रयासों के बारे में श्री राजनाथ सिंह ने प्रयोगशाला से आग्रह किया कि वह एक राष्ट्रव्यापी मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करते हुए अगली पीढ़ी के इंजनों पर ध्यान केंद्रित करे और साथ ही एयरो इंजनों में आत्मनिर्भरता हासिल करे। उन्होंने यह भी कहा कि हम उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (एएमसीए) के डिजाइन और विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने अतीत में एयरो इंजनों के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के कई प्रयास किए हैं। अब उन प्रयासों को पूरा करने का समय आ गया है। हम खुद को केवल पांचवीं पीढ़ी के इंजनों तक सीमित नहीं रख सकते । हमें जल्द से जल्द छठी पीढ़ी की उन्नत तकनीकों का विकास शुरू करना होगा। इन पर शोध समय की मांग है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और नई सामग्रियों का उपयोग बढ़ रहा है। हमें इस क्षेत्र में अग्रणी बने रहना होगा।

रक्षा मंत्री ने एयरो इंजन के विकास को एक अत्यंत जटिल कार्य बताया। इसमें ऊष्मागतिकी, पदार्थ विज्ञान, द्रव यांत्रिकी और उन्नत यांत्रिक अभियांत्रिकी का समावेश होता है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों को भी अगली पीढ़ी के इंजन विकसित करने में अक्सर 25-30 साल लग जाते हैं, और उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों से देश की रणनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समयसीमा को कम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमें यह मानकर चलना होगा कि 20 साल बीत चुके हैं और अब हमारे पास केवल 5-7 साल बचे हैं। उन्होंने इसे राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप कार्रवाई का आह्वान बताया।

ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान रक्षा बलों ने रक्षा क्षेत्र में देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि संचार प्रणाली हो, निगरानी उपकरण हों या आक्रमण हथियार, सब कुछ स्वदेशी था। इससे हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ा और नागरिकों में गर्व की भावना पैदा हुई। बदलती चुनौतियों को देखते हुए, स्वदेशी पद्धतियों पर अधिक ध्यान देना और अपनी सेनाओं को विश्व स्तरीय प्रणालियां और उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

रक्षा मंत्री ने एयरो इंजन विकास के लिए ब्रिटेन के साथ संयुक्त अध्ययन की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय एयरो इंजन मिशन के तहत फ्रांस के साथ भी एयरो इंजन के लिए यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही एयरो इंजन प्रौद्योगिकी में काफी उन्नत हैं। ये सहयोग न केवल हमें नई प्रौद्योगिकियों को सीखने का अवसर प्रदान करेंगे, बल्कि पिछले दशकों में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को समझने में भी मदद करेंगे।

आधार ऐप की बढ़ती लोकप्रियता और दैनिक उपयोगिता, ऐप के माध्यम से 1 मिलियन लोगों ने घर बैठे मोबाइल नंबर अपडेट किया

यूआईडीएआई के आधार ऐप को मिली शानदार प्रतिक्रिया, डाउनलोड्स की संख्या 14 मिलियन के पार

आधार ऐप डेटा मिनिमाइजेशन, कंसेंट कंट्रोल और सेलेक्टिव शेयरिंग जैसी कई प्रमुख विशेषताओं को बढ़ावा देता है

(जीएनएस)।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआइई) के नए आधार ऐप को लेकर आम जनता में भारी उत्साह देखा जा रहा है। ऐप को अपनाने की यह तेज गति सुरक्षित, डिजिटल और सुविधाजनक आधार सेवाओं के प्रति नागरिकों के बढ़ते भरोसे को दशार्ती है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआइई) के नए आधार ऐप ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब तक इसे लगभग 14 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। यह सफलता देश भर में आधार सेवाओं को अधिक सुलभ, उपयोगकर्ता के अनुकूल और तुरंत उपलब्ध कराने में इस ऐप की महत्वपूर्ण भूमिका को दशार्ती है।

आधार ऐप एक नेक्स्ट-जेनरेशन का मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसे आधार संख्या धारकों (एएनएच) को अपनी डिजिटल पहचान रखने, साझा करने, दिखाने और सत्यापित करने के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और गोपनीयता-केंद्रित तरीका प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एंड्रॉइड और एप्पल आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

28 जनवरी को राष्ट्र को समर्पित किए गए इस नए ऐप को औसतन प्रतिदिन 1,00,000 से अधिक लोग डाउनलोड कर रहे हैं। इस ऐप की बढ़ती उपयोगिता ने आधार सेवाओं को निवासियों के लिए घर बैठे ही सुलभ बना दिया है। अब तक यह ऐप 1 मिलियन निवासियों को अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने में मदद कर चुका है। वहीं 3,57,000 आधार धारकों ने ऐप के जरिए अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक या अनलॉक किया है। इसी तरह, लगभग 8,00,000 निवासियों ने नए ऐप का उपयोग करके अपना ई-आधार डाउनलोड किया है।

इस ऐप में कई आधुनिक और उन्नत सुविधाएँ शामिल हैं, जैसे प्रेजेंस के प्रूफ के तौर पर फेस वेरिफिकेशन, सिंगल क्लिक में बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक, ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को देखने की सुविधा और कॉन्टैक्ट डिटेल्स को आसानी से साझा करने के लिए दफ्-आधारित कॉन्टैक्ट कार्ड।

सभी यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया यह आधार ऐप, दैनिक जीवन के कई महत्वपूर्ण कार्यों में सहायक है। इसके माध्यम से होटल में चेक-इन के दौरान ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटी (ओवीएसई) क्यूआर कोड स्कैनिंग, उम्र का सत्यापन, अस्पतालों में भर्ती, कार्यक्रमों में प्रवेश और गिग वर्कर्स व सर्विस पार्टनर्स के सत्यापन जैसे कई कार्य सुगम हो गए हैं। इसके साथ ही, यूआईडीएआई एक ऐसा ऑफलाइन वेरिफिकेशन इकोसिस्टम भी विकसित कर रहा है, जिससे विभिन्न संस्थाएं पंजीकृत होकर आधार ऐप की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगी और सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाया जा सकेगा।

यह ऐप एक ही डिवाइस पर पांच आधार प्रोफाइल तक के प्रबंधन की

डिजाइन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर आधारित चिप डिजाइन स्टार्टअप्स पर बड़े निवेशकों का फोकस जारी

सी2आई सेमीकंडक्टर्स ने पीक एक्सवी पार्टनर्स के नेतृत्व में 15 मिलियन डॉलर की सीरीज फंडिंग जुटाई - किसी भारतीय सेमीकंडक्टर स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई अब तक की सबसे बड़ी फंडिंग

सी2आई ऊर्जा कुशल और विश्वसनीय उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए इंटेलिजेंट पावर-मैनेजमेंट चिप डिजाइन कर रही है

(जीएनएस)।

भारत का सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना के अंतर्गत समर्थित स्टार्टअप निवेशकों और उपयोगकताओं दोनों की ओर से बढ़ती रुचि आकर्षित कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर उद्यमों में परंपरागत रूप से राजस्व प्राप्त होने से पहले विकास की लंबी अवधि, पर्याप्त अनुसंधान एवं विकास निवेश और उच्च तकनीकी जोखिम शामिल होते हैं, जो अक्सर शुरूआती चरण के निवेशकों को सतर्क कर देते हैं। परिणामस्वरूप वर्ष 2021 से पहले देश में इस क्षेत्र में उद्यम पूंजी निवेश सीमित रहा।

सरकार की डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना जिसकी घोषणा वर्ष 2022 में की गई थी, वित्तीय सहायता, उन्नत ईडीए टूल्स, बौद्धिक संपदा कोर आदि तक पहुंच और सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन के बारे में व्यापक इकोसिस्टम जागरूकता प्रदान करके प्रारंभिक जोखिम को कम करने के माध्यम से इस चुनौती का समाधान करती है। स्टार्टअप्स को तकनीकी और उद्योग विशेषज्ञों से बनी एक सक्षम विशेषज्ञ समिति द्वारा कठोर स्क्रीनिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से शामिल किया जाता है, जिससे विश्वसनीय डीप-टेक कंपनियों को सहायता सुनिश्चित होती है। यह सुनियोजित हस्तक्षेप निवेशकों के विश्वास और व्यावसायिक व्यवहार्यता में लगातार सुधार करता है, जिससे निवेशक डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव समर्थित स्टार्टअप्स का सक्रिय रूप से मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित होते हैं।

सी2आई सेमीकंडक्टर्स

टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, नेशनल सेमीकंडक्टर और मैक्सिम इंटीग्रेटेड जैसी वैश्विक स्तर की अग्रणी कंपनियों में दशकों का अनुभव रखने वाली संस्थापक टीम द्वारा 5 जून 2024 को बेंगलुरु में स्थापित, सी2आई सेमीकंडक्टर्स को बाद में डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता और उन्नत चिप डिजाइन उपकरणों तक पहुंच के लिए 1 नवंबर 2024 से मंजूरी मिल गई।

सेमीकंडक्टर उद्योग के दिग्गज गणपति सुब्रमण्यम, जो याली कैपिटल के संस्थापक प्रबंध भागीदार हैं, के बोर्ड में शामिल होने के साथ, सी2आई की अगली पीढ़ी के एआई डेटा केंद्रों और क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पावर-मैनेजमेंट सेमीकंडक्टर समाधान विकसित कर रही है।

सीएक्यूएम ने 2026 में गेहूं की पराली जलाने की समस्या को खत्म करने के लिए कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में व्यापक वैधानिक निर्देश जारी किए

(जीएनएस)।

एनसीआर और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने वैधानिक निर्देश जारी किए हैं, जिसमें 2026 की कटाई के मौसम के दौरान गेहूं की पराली को जलाने की रोकथाम और उसकी समस्या को खत्म करने के लिए राज्य कार्य योजनाओं के समन्वित और समयबद्ध कार्यान्वयन को जरूरी बताया गया है। यह निर्देश पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को जारी किए गए हैं, और इसके साथ-साथ जीएनसीटीडी और राजस्थान से भी मदद की अपेक्षा की गई है।

आयोग ने कहा कि कृषि अवशेष जलाने से स्थानीय स्तर पर तथा एनसीआर एवं आस-पास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है, इसलिए इसके लिए क्रमबद्ध तरीके से मौसमी तैयारी की आवश्यकता है। इसरो/आईएआरआई द्वारा स्थापित मानक प्रोटोकॉल के अनुसार, गेहूं की कटाई के मौसम (1 अप्रैल से 31 मई 2025) के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों में आग की घटनाओं की संख्या क्रमशः 10207, 1832 और 259 रही। गेहूं की कटाई के मौसम (अप्रैल-मई 2025) के दौरान उपग्रह-आधारित मॉनिटरिंग में पूरे क्षेत्र में आग लगने की ऐसी घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया, जिससे धान के मौसम के मौजूदा उपायों के साथ-साथ गेहूं के मौसम में लक्षित उपायों की आवश्यकताओं पर जोर दिया गया।

आयोग ने फसल अवशेष जलाने को नियंत्रित/समाप्त करने के लिए संबंधित राज्यों को एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की थी और उन्हें रूपरेखा के मुख्य हिस्सों के आधार पर विस्तृत राज्य-विशिष्ट कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, गेहूं की पराली जलाने के मुद्दे पर 22 दिसंबर, 2025 को आयोग की 26वीं बैठक और उसके बाद पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ हुई बैठकों में विस्तार से चर्चा की गई थी, जहां राज्य सरकारों ने अपनी कार्ययोजना पेश की और आयोग ने इन राज्यों को अपनी कार्य-योजनाओं को और बेहतर बनाने की सलाह दी।

तदनुसार, आयोग ने अपनी निर्देश संख्या 96 के माध्यम से, संबंधित राज्यों को व्यवहारिक विकल्प सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट सुविधाजनक उपायों के साथ गेहूं के भूसे को जलाने को रोकने के लिए अपनी संबंधित कार्य योजनाओं को कार्यान्वित करने का निर्देश दिया है। आयोग ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को निर्देश दिया है किः गेहूं की पराली जलाने की समस्या को खत्म करने

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 का उल्लंघन करने वाले खिलौने बेचने वाली ई-कॉमर्स संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की

भारतीय मानक ब्यूरो मानकों के अनुरूप न होने वाले खिलौनों की बिक्री के लिए स्नैपडील पर 5 लाख रुपए का जुमार्ना लगाया

(जीएनएस)।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने अनिवार्य खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हुए खिलौने बेचने वाले ई-कॉमर्स संस्थाओं और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस सम्बंध में, सीसीपीए ने स्नैपडील (ऐस वेक्टर लिमिटेड) पर अनुचित व्यापार तौर-तरीकों और भ्रामक विज्ञापनों का दोषी पाये जाने के कारण 5 पांच लाख रुपये का जुमार्ना लगाया है। स्नैपडील ने उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करते हुए अपने प्लेटफॉर्म पर बीआईएस मानकों के अनुरूप न होने वाले खिलौनों की बिक्री को बढ़ावा दिया था।

मुख्य आयुक्त श्रीमती निधि खरे और आयुक्त श्री अनुपम मिश्र के नेतृत्व में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य बीआईएस मानकों के अनुरूप न होने वाले खिलौनों की बिक्री के लिए स्नैपडील (ऐस वेक्टर लिमिटेड) के खिलाफ अंतिम आदेश जारी किया है।

सीसीपीए ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और पता लगाया कि स्नैपडील पर खिलौने , खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 का उल्लंघन करते हुए बेचे जा रहे थे जो 1 जनवरी, 2021 से अनिवार्य हो गया था। विस्तृत जांच में कई गंभीर खामियां सामने आईंः

नियमों का निरंतर उल्लंघनः सूची से हटाए जाने के दावों के बावजूद, नियमों का उल्लंघन करने वाले खिलौने दिसंबर 2025 तक भी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहे।

बेचे गए उत्पादों से व्यावसायिक लाभः स्नैपडील ने केवल दो पहचाने गए विक्रेताओं - स्टैलियन ट्रेडिंग कंपनी और थ्रिफ्टकार्ट - के माध्यम से इन गैर-अनुरूप खिलौनों की बिक्री से 41,032 रुपए की फीस अर्जित की।

पारदर्शिता का अभावः कई सूचियों में निमार्ता का नाम, पता और अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन संख्या जैसी आवश्यक जानकारी का अभाव था।

अपर्याप्त उचित सावधानीः प्लेटफॉर्म ने स्वतंत्र सत्यापन के बिना पूरी तरह से विक्रेताओं की स्व-घोषणाओं पर भरोसा किया, इसे सीसीपीए ने खतरनाक उत्पादों की सूची को रोकने के लिए "अपर्याप्त" माना।

स्नैपडील ने अपना बचाव करते हुए कहा कि यह एक शॉपिंग मॉल की तरह "मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स इकाई" के रूप में कार्य करता है। सीसीपीए ने इस तुलना को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि स्नैपडील निम्नलिखित तरीकों से लेन-देन पर "पर्याप्त नियंत्रण" रखता हैः

"तूफान सेल" और "डील ऑफ द डे" जैसी प्लेटफॉर्म-व्यापी प्रचार बिक्री का प्रबंधन करना ।

"सर्वोत्तम मूल्य पर उत्कृष्ट गुणवत्ता" जैसे गुणवत्ता आश्वासन वाले टैग लगाना, जो कि बीआईएस मानक का पालन न करने वाले उत्पादों पर लागू होने पर झूठी गारंटी के रूप में कार्य करता है।

रसद, धनवापसी और प्रतिस्थापन योजनाओं को नियंत्रित करना।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण पता लगाया कि 'खरीददार सावधान रहे' से 'विक्रेता सावधान रहे' के सिद्धांत में बदलाव से उत्पाद सुरक्षा सुनिश्चित करने का भार विक्रेता और सुविधा प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म दोनों पर आ जाता है। परिणामस्वरूप, प्लेटफॉर्म की यह जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि सूचीबद्ध प्रत्येक उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है, जैसे कि खिलौनों के लिए बीआईएस प्रमाणन और पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाली किसी भी सेवा में कमी या माल में खराबी के लिए वह परोक्ष रूप से उत्तरदायी रहता है।

केरल चुनाव से पहले दिल्ली में बड़ी हलचल! पीएम मोदी से मिले ग्रैंड मुफ्ती, क्या दक्षिण में बदलेगा समीकरण?

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबकर अहमद साहब के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और शिक्षा सुधार में उनके प्रयास सराहनीय हैं।'

केरल विधानसभा चुनाव 2026 से ठीक पहले दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबकर अहमद ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक को केरल की सियासत में बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय (खासकर मुस्लिम वोट बैंक) चुनावी समीकरण बदल सकता है। मुलाकात में सामाजिक सद्भाव, शिक्षा सुधार,

अल्पसंख्यक कल्याण और समावेशी विकास पर विस्तृत चर्चा हुई।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबकर अहमद साहब के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और शिक्षा सुधार में उनके प्रयास सराहनीय हैं।'

ग्रैंड मुफ्ती ने बैठक के बाद कहा, -भारत में मुस्लिम समुदाय पूरी तरह सुरक्षित है। कोई बाधा या समस्या नहीं है। हम सब मिलकर राष्ट्र की बेहतरी के लिए काम करेंगे।' उन्होंने अपने हालिया केरल दौरे 'विद ह्यूमैनिटी' के दौरान विभिन्न वर्गों से प्राप्त चिंताओं और मांगों को प्रधानमंत्री के समक्ष रखा। रमजान के संदेश भी साझा किए गए।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री सतीश गोलचा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक शांति, सेवा और न्याय के संकल्प को चरितार्थ करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ ही देश के लोकतंत्र की धड़कन और अस्मिता का केन्द्र है। राजधानी होने के नाते दिल्ली की सुरक्षा का दायित्व सभी वैश्विक मानांकों में उच्चतम होना बेहद जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि दिल्ली में कई प्रकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालय और निवास के कारण दिल्ली पुलिस की ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने हमेशा आगे रहते हुए प्रखरता और सफलता के साथ अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है।

श्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस को और मजबूत करने के लिए आज स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड मुख्यालय का ई-शिलान्यास हुआ है। लगभग 368 करोड़ रूपए की लागत से स्पेशल सेल का यह इंटीग्रेटेड मुख्यालय नार्कोटिक्स और आतंकवाद से निपटने में देश का सबसे आधुनिक केन्द्र बनेगा। उन्होंने कहा कि यह मुख्यालय अत्याधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज, वॉर रूम, साइबर लैब, प्रशिक्षण हॉल सहित कई प्रकार के आधुनिक उपकरणों से लैस होगा और देशभर के पुलिसबलों के लिए एक आदर्श स्पेशल सेल मुख्यालय बनेगा। श्री शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नशीले पदार्थों के सिंडिकेट्स, जाली भारतीय करेंसी नोट्स, जटिल साइबर अपराध, संगठित अपराध की साथ ही न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश की कई बड़ी आतंकी घटनाओं की जांच में सफल और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज दिल्ली पुलिस की 10 नई परियोजनाओं का शिलान्यास और लगभग 857 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित सेफ सिटी प्रोजेक्ट के पहले चरण का लोकार्पण भी हुआ है। इसके तहत आधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन और कम्प्यूटर सेंटर (उ4क) को दिल्ली की जनता को समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि 10 हजार कैमरों से दिल्ली को जोड़ने के कार्यक्रम के प्रथम चरण में 2100 कैमरे लाइव जुड़ चुके हैं और पहले से मौजूद 15 हजार से अधिक कैमरों को भी इसके साथ जोड़ने का काम पूरा हो चुका है। श्री शाह ने कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में दिल्ली की सुरक्षा को बहुत आगे ले जाएगा।

क्षेत्रीय कार्यक्रम सह कार्यशाला का आयोजन 17 फरवरी 2026 को जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (एसकेआईसीसी) में किया जाएगा

(जीएनएस)।

क्षेत्रीय कार्यक्रम सह कार्यशाला का आयोजन 17 फरवरी 2026 को श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (एसकेआईसीसी) में किया जाएगा।

इस क्षेत्रीय सम्मेलन सह कार्यशाला 2026 का आयोजन न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करने (डीआईएसएचए- दिशा) की टेली-लॉ पहल के अंतर्गत किया जा रहा है। केंद्रीय क्षेत्र की इस योजना को भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय का न्याय विभाग कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यशाला का आयोजन 17 फरवरी 2026 को दोपहर 12:00 बजे से जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (एसकेआईसीसी) में होगा।

इस कार्यशाला का आयोजन न्याय विभाग प्रौद्योगिकी-सक्षम कानूनी सेवाओं के माध्यम से न्याय तक पहुंच को मजबूत करने और प्रमुख हितधारकों के बीच जानकारीपूर्ण विचार-विमर्श को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा है।

इस कार्यक्रम का शुभारम्भ देश के राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" के सामूहिक गायन से होगा। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। यह भारत के इतिहास में इसकी भावना और अद्वितीय भूमिका का जश्न मनाने के लिए है।

इस कार्यक्रम में न्याय विभाग (डीओजे) की 'दिशा योजना' के प्रमुख प्रचार और कार्यान्वयन चैनलों पर भी प्रकाश डाला जाएगा, जिसका उद्देश्य देश भर में कानूनी साक्षरता और न्याय तक पहुंच को मजबूत करना है। कार्यक्रम के एक खंड, "दिशा योजना के आयामः सुगम एवं सुलभ न्याय तक पहुंच" में सामुदायिक प्रचार कार्यक्रमों, डिजिटल अभियानों और शैक्षणिक संस्थानों एवं नागरिक समाज संगठनों के साथ साझेदारी के माध्यम से कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने की योजना की पहलों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें सरल और प्रौद्योगिकी-सक्षम प्लेटफार्मों के माध्यम से हाशिए पर पड़े और कमजोर समुदायों तक पहुंचने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर में दिशा योजना की उपस्थिति और उसके कार्यों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। "जम्मू-कश्मीर में दिशाः एक झलक" शीर्षक वाले खंड में, इस केंद्र शासित प्रदेश में कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने और न्याय तक पहुंच में सुधार लाने के लिए योजना की पहलों पर प्रकाश डाला जाएगा।

इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण न्याय विभाग (डीओजे) की दिशा योजना से जुड़े उन उपलब्धि हासिल करने वालों का अभिनंदन होगा, जिन्होंने कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देने और न्याय तक पहुंच में सुधार लाने में अहम योगदान दिया है। समारोह में उन हस्तियों और संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने समर्पित जनसंपर्क और सामुदायिक सहभागिता प्रयासों के माध्यम से योजना के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया है।

इसके अलावा, इस कार्यक्रम में दिशा का वार्षिक ई-कैलेंडर भी जारी किया जाएगा, जो पूरे वर्ष न्याय विभाग की प्रमुख गतिविधियों, अभियानों और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए एक संरचित रोडमैप के रूप में काम करेगा।

इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में वेव्स क्रिएटर्स कॉर्नर में 51 स्टार्टअप एआई नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे

वेव्स क्रिएटर्स कॉर्नर भारत के अगली पीढ़ी के मीडिया प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तकों को सुर्खियों में लाएगा

(जीएनएस)।

भारत के उभरते मीडिया और मनोरंजन नवाचार इकोसिस्टम को एक बड़ा प्रोत्साहन देते हुए, एवीजीसी-एक्सआर (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी) और मीडिया टेक क्षेत्र के 51 होनहार स्टार्टअप, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित वेव्स क्रिएटर्स कॉर्नर में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 के दौरान अपने उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेंगे। यह एक्सपो 16 से 20 फरवरी 2026 तक

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा।

इन स्टार्टअप्स की भागीदारी वेवएक्स के सहयोग से संभव हो पाई है, जो भारत की नवाचार-आधारित रचनात्मक अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रहा है। वेव्स क्रिएटर्स कॉर्नर स्टार्टअप्स के लिए एक गतिशील मंच के रूप में कार्य करेगा, जहां वे उद्योग जगत के नेताओं, निवेशकों, नीति निमार्ताओं और वैश्विक हितधारकों के समक्ष एआई-संचालित समाधान, आकर्षक कहानी कहने के प्रारूप, गेमिंग नवाचार, वर्चुअल प्रोडक्शन टूल्स और अगली पीढ़ी की कंटेंट टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर सकेंगे।

यह चयनित समूह भारत के तेजी से बढ़ते एवीजीसी-एक्सआर परिदृश्य के विविध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। एआई-सक्षम एनिमेशन पाइपलाइन और रीयल-टाइम रेंडरिंग इंजन से लेकर आकर्षक एक्सआर अनुभव और गेमिफाइड लर्निंग प्लेटफॉर्म तक, प्रदर्शित स्टार्टअप्स कंटेंट निर्माण, वितरण और दर्शकों के जुड़ाव को पुनर्परिभाषित करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी क्षमता को दर्शाते हैं।

इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में, "वेव्स क्रिएटर्स कॉर्नर" में "भारत एआई के लिए विचार" की एक भविष्यवादी श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी, जो मीडिया नवाचार को दर्शकों के साथ गहन जुड़ाव के साथ जोड़ती है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने हज 2026 के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए अभिविन्यास-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

(जीएनएस)।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हज 2026 के लिए हज प्रतिनिधियों के लिए अभिविन्यास-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने किया, जो हज 2026 की तैयारियों की औपचारिक शुरूआत का प्रतीक है, जिसमें करीब 1.75 लाख भारतीय तीर्थयात्री तीर्थयात्रा करेंगे। प्रतिनिधियों को सऊदी अरब में ढाई महीने की अवधि के लिए सीजीआई की देखरेख में तैनात किया जाएगा, ताकि तीर्थयात्रियों को जरुरी प्रशासनिक और चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके। प्रतिनिधियों का चयन विभिन्न सरकारी संगठनों से किया गया है, जो सभी तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित, कुशल और सहानुभूतिपूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के समन्वित राष्ट्रीय प्रयास को दशार्ता है।

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने अपने उद्घाटन भाषण में इस बात पर जोर दिया कि हज प्रबंधन विदेशों में भारत द्वारा किए जाने वाले सबसे बड़े और सबसे जटिल रसद अभियानों में से एक है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को लगभग 1.75 लाख तीर्थयात्रियों की सेवा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वे वास्तव में सऊदी अरब में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मंत्री जी ने हाल के सालों में शुरू किए गए प्रमुख कल्याणकारी उपायों और सुधारों पर प्रकाश डाला, जिनमें बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के लिए विशेष सुविधाएँ और उनके साथ यात्रा करने वालों के लिए व्यवस्था, साथ ही बिना मेहरम के यात्रा करने वाली महिला तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएँ शामिल हैं। श्री कुरियन ने गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालयों को शामिल करते हुए समग्र सरकारी दृष्टिकोण के तहत मंत्रालय के मजबूत समन्वय और हज 2026 के लिए लगभग 600 सरकारी अधिकारियों की तैनाती पर भी बल दिया।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉ. सी.एस. कुमार ने अपने संबोधन में सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत विश्व स्तर पर हज यात्रियों के सबसे बड़े योगदानकताओं में से एक है, इस साल करीब 1.75 लाख तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि हज 2026 की तैयारियों को सुव्यवस्थित ढंग से पूरा किया गया है। उन्होंने समय पर व्यवस्था सुनिश्चित करने में विदेश मंत्रालय, सऊदी अधिकारियों, जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास और अन्य हितधारकों के सहयोग की सराहना की।

डॉ. कुमार ने जमीनी हकीकतों से अवगत कराने के लिए चरणबद्ध और व्यवस्थित प्रशिक्षण और प्रतिनिधियों को परिचालन प्रक्रियाओं से बेहतर ढंग से परिचित कराने के लिए ऑडियो-विजुअल मॉड्यूल के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म और एआई-सक्षम प्रणालियों सहित प्रौद्योगिकी के अधिक एकीकरण, फील्ड अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के जरिए लगातार सुधार और विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते समय प्रतिनिधियों द्वारा सांस्कृतिक संवेदनशीलता, अनुशासन और गरिमापूर्ण आचरण की आवश्यकता पर भी बल दिया।

डोपिंग रोधी समन्वय और प्रवर्तन बढ़ाने के उपायों की राष्ट्रीय अनुपालन प्लेटफॉर्म द्वारा समीक्षा

खेल सचिव की अध्यक्षता में डोपिंग रोधी ढांचे मजबूत करने हेतु राष्ट्रीय अनुपालन प्लेटफॉर्म की चौथी बैठक आयोजित डोपिंग रोकथाम और स्वच्छ खेल को बढ़ावा देने के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय तेज

(जीएनएस)।

खेलों में प्रदर्शन बेहतर बनाने के लिए प्रतिबंधित शक्तिवर्धक दवाओं, हार्मोन या अन्य अनैतिक उपायों को रोकने संबंधी डोपिंग रोधी मुद्दों पर विचार के लिए आज युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अनुपालन प्लेटफॉर्म (एनसीपी) की चौथी बैठक हुई।

खेल सचिव श्री हरि रंजन राव ने विभिन्न एजेंसियों की डोपिंग रोधी पहल की व्यापक समीक्षा की और डोपिंग रोकथाम के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय और मजबूत बनाने तथा देश में स्वच्छ और निष्पक्ष खेल प्रथाओं को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार-विमर्श किया।

श्री राव ने अनजाने में शक्तिवर्धक दवा लेने संबंधी डोपिंग के जोखिम कम करने और स्वच्छ खेल प्रचलन के लिए समन्वित प्रवर्तन कार्रवाई, सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला निगरानी और जागरूकता बढ़ाने के महत्व का उल्लेख किया।

बैठक में आगामी चचाओं में नियामक निरीक्षण बढ़ाने, जांच और निगरानी तंत्र मजबूत करने और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच प्रभावी खुफिया जानकारी साझाकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

बैठक में दूषित और गलत लेबल वाले पोषण पूरक, निर्धारित दवाओं के दुरुपयोग और प्रतिबंधित और गैर-अनुमोदित पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री और प्रचार सहित उभरती चुनौतियों पर भी चर्चा हुई।

इसके अलावा संबद्ध एजेंसियों ने निगरानी बढ़ाने, नमूना परीक्षण में बढ़ोतरी, प्रयोगशाला क्षमता के मूल्यांकन और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के तालमेल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा पोषण पूरक की जांच की आवश्यकता भी बताई।

बैठक में एथलीटों और प्रशिक्षकों के लिए संरचित डोपिंग रोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, सुलभ शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने और भारत में औषधियों के आयात, निर्माण और वितरण को नियंत्रित करने वाले ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940, विशेषकर केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही बेची जा सकने वाली अनुसूची एच की दवाओं से संबंधित प्रावधानों के कठोर प्रवर्तन सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया गया।

बैठक में प्रतिबंधित शक्तिवर्धक दवाओं के इस्तेमाल/डोपिंग को स्रोत पर ही रोकने, अंतरराष्ट्रीय डोपिंग रोधी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित

इस्पात मंत्रालय ने मंडी गोविंदगढ़ में चिंतन शिविर का आयोजन किया जिसमें द्वितीयक इस्पात क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए हरित इस्पात पर विचार-विमर्श किया गया

सरकार, औद्योगिक उद्यम और उद्योगपतियों द्वितीयक इस्पात के लिए हरित इस्पात उत्पादन के महत्व, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए

(जीएनएस)।

मंडी गोबिंदगढ़ स्थित राष्ट्रीय द्वितीयक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएसएसटी) में एक दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही देश में हरित इस्पात उत्पादन पर विचार-विमर्श की शुरूआत हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन इस्पात मंत्रालय के सचिव श्री संदीप पौंड्रिक ने किया। अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, संयुक्त सचिव और इस्पात मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ-साथ औद्योगिक उद्यमों, तकनीकी विशेषज्ञों, उद्योग संघों और द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

इस्पात सचिव श्री संदीप पौंड्रिक ने अपने संबोधन में द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डाला, जो देश में कुल इस्पात उत्पादन का लगभग 47 प्रतिशत योगदान देता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां उत्पादन, खपत और स्थापित क्षमता में प्रतिवर्ष 8-10 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। उन्होंने द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के विकास में एनआईएसटी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने सभा को सूचित किया कि एनआईएसटी देश के विभिन्न इस्पात

समूहों में महीने में दो बार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। एनआईएसटी को हरित इस्पात प्रमाणन के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है और इसने अब तक 76 उद्योगों (10.98 मीट्रिक टन) को हरित इस्पात प्रमाणपत्र जारी किए हैं। उन्होंने प्रतिभागियों को सूचित किया कि इस्पात मंत्रालय प्रौद्योगिकी सुधार और परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए द्वितीयक इस्पात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना पर काम कर रहा है। इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव और एनआईएसटी के अध्यक्ष श्री दया निधान पांडे ने भी द्वितीयक इस्पात क्षेत्र की क्षमता निर्माण में एनआईएसटी की भूमिका पर प्रकाश डाला।

चिंतन शिविर-2026 में इस्पात क्षेत्र में उभरती कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित विचार-विमर्श किया गया जिसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में हरित हाइड्रोजन का उपयोग और रोटरी भट्टी आधारित लौह निर्माण में हाइड्रोजन का उपयोग शामिल है। सत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करने और ऑफ-पीक नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए द्वितीयक इस्पात क्षेत्र में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की तैनाती पर भी चर्चा हुई। चचाओं में जल गैस को अपचायक के रूप में उपयोग करके ऊर्ध्वाधर शाफ्ट आधारित डीआरआई उत्पादन पर प्रकाश डाला गया जिससे कम उत्सर्जन के साथ ईंधन और कच्चे माल में लचीलापन संभव हो पाता है। मिश्र धातु इस्पात उत्पादों के निर्यात अवसरों की समीक्षा की गई, साथ ही कार्बन सीमा समायोजन तंत्र से उत्पन्न चुनौतियों पर भी विचार किया गया।

चचाओं में हरित इस्पात की आगामी प्रौद्योगिकियों, नई उपलब्धियों और हरित इस्पात उत्पादन की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। विचार-विमर्श में नीति निमार्ताओं, उद्योगपतियों और तकनीकी विशेषज्ञों के दृष्टिकोणों को एक साथ लाया गया जिसका उद्देश्य हरित इस्पात उत्पादन और सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ना था।

अंतरराष्ट्रीय बाँध सुरक्षा सम्मेलन 2026 बेंगलुरु में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ

बाँध सुरक्षा हेतु प्रौद्योगिकी, जवाबदेही, जोखिम-आधारित निर्णय-प्रक्रिया तथा जलवायु-सहिष्णु दृष्टिकोणों को रेखांकित किया गया

(जीएनएस)।

दो-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बाँध सुरक्षा सम्मेलन (आईसीडीएस) 2026 – जिसका शुभारंभ 13 फरवरी 2026 को उच्च-स्तरीय उद्घाटन तथा पूर्ण अधिवेशन कार्यक्रम के साथ हुआ था और जिसमें ऐसे तकनीकी एवं औद्योगिक सत्र आयोजित किए गए, जिन्होंने सम्मेलन की विचार-विमर्श प्रक्रिया के लिए रणनीतिक संदर्भ प्रदान किया – व्यापक चर्चा तथा ज्ञान के आदान-प्रदान के उपरांत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

सम्मेलन के पहले दिन वरिष्ठ सरकारी नेतृत्वकताओं, विनियामकों, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों तथा क्षेत्र के व्यावहारिक विशेषज्ञों ने भाग लिया और भारत में बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 तथा बाँध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के अंतर्गत विकसित हो रहे बाँध सुरक्षा ढाँचे पर बल दिया। विचार-विमर्श के दौरान जलवायु सहिष्णुता, समन्वित जलाशय संचालन तथा संस्थागत क्षमता विकास को देश में बाँध सुरक्षा शासन को सुदृढ़ करने हेतु महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया गया।

सम्मेलन के दूसरे दिन गहन तकनीकी तथा औद्योगिक सत्रों की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जिनमें बाँध पुनर्वास, गाद (सेडिमेंट) प्रबंधन, जोखिम-आधारित मूल्यांकन तथा जलवायु सहिष्णुता से संबंधित वैश्विक एवं राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों को रेखांकित किया गया। सरकारी एजेंसियों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों,

शैक्षिक जगत तथा उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों ने साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोणों तथा क्षेत्र में परीक्षित समाधानों को साझा किया, जिनका उद्देश्य पुरानी होती जल अवसंरचना की सुरक्षा तथा स्थिरता को सुदृढ़ करना है।

पुराने होते बाँधों पर तकनीकी सत्रः अत्याधुनिक पुनर्वास उपाय

पद्धतियों में इस बात पर बल दिया गया कि, चूँकि अनेक बाँध अपनी अभिकल्पित आयु के निकट पहुँच रहे हैं या उसे पार कर रहे हैं, कठोर गुणवत्ता आश्वासन तथा सुदृढ़ शासन व्यवस्था द्वारा समर्थित वैज्ञानिक एवं जोखिम-आधारित पुनर्वास एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिकता बन गया है।

जलाशयों में गाद प्रबंधन पर तकनीकी सत्र में जलाशयों में गाद को बाँध सुरक्षा तथा जल सुरक्षा के लिए एक दीर्घकालिक खतरे के रूप में रेखांकित किया गया। इस सत्र में प्रतिक्रियात्मक उपायों से आगे बढ़कर समेकित एवं निवारक गाद प्रबंधन प्रक्रियाएं अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिसे जलग्रहण क्षेत्र उपचार, दूरसंवेदी प्रौद्योगिकी तथा नीति-समर्थित क्रियान्वयन द्वारा सुदृढ़ किया जा सके।

सुरक्षित बाँधों हेतु जोखिम-आधारित निर्णय-निर्धारण पर तकनीकी सत्र में संरचित जोखिम रूपरेखाओं के माध्यम से बाँध सुरक्षा विनियमन तथा आपातकालीन तैयारी को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस सत्र में रेखांकित किया गया कि सरलीकृत जोखिम परीक्षण, बाँध-विफलता आकलन उपकरण तथा जलवायु-संवेदनशील कार्यप्रणालियाँ, बड़े बाँध समूहों में प्राथमिकता निर्धारण तथा साक्ष्य-आधारित निर्णय-निर्धारण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

बाँधों की जलवैज्ञानिक सुरक्षा तथा बाढ़ प्रबंधन हेतु समन्वित जलाशय संचालन पर तकनीकी सत्र में पूवार्नुमान-आधारित तथा नदी बेसिन स्तर पर समन्वित जलाशय संचालन के महत्व को रेखांकित किया गया। विचार-विमर्श में इस बात पर बल दिया गया कि बढ़ती जलवायु परिवर्तनशीलता की परिस्थितियों में बाढ़ तथा सूखे के प्रभावी प्रबंधन हेतु गतिशील नियम वक्र, रिअल टाइम डेटा शेयरिंग तथा निर्णय-सहायक प्रणालियाँ अत्यंत अनिवार्य हैं।

बाँध संकट एवं विफलताओं से प्राप्त सबकों पर तकनीकी सत्र में पुनः यह पुष्टि की गई कि बाँधों में उत्पन्न संकट तथा विफलता की घटनाएँ निरंतर इस बात की आवश्यकता को इंगित करती हैं कि अभियांत्रिकीय सतर्कता, अभिकल्पना तथा निर्माण मानकों का कठोर अनुपालन, प्रभावी आपातकालीन कार्ययोजनाएँ तथा सुदृढ़ संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

बाँध सुरक्षा निगरानी प्रणालियों की प्रगति पर औद्योगिक सत्र में इस बात को रेखांकित किया गया कि सत्यापित रिअल टाइम आँकड़े, डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा उन्नत संवेदन प्रौद्योगिकियाँ बाँध सुरक्षा निगरानी को रूपांतरित कर रही हैं8